

Daily Current Affairs 23/07/2021

1. भारत में जल क्षेत्र के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां



चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र ने जल क्षेत्र में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से पैदा हुए अवसरों पर विस्तृत रिपोर्ट भू-स्थानिक

प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन द एसोसिएशन ऑफ जियोस्पेशियल इंडस्ट्रीज ने 'पोटेंशियल ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजिज फॉर द वाटर सेक्टर इन इंडिया' यानी भारत में जल क्षेत्र के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों की क्षमता

- जनसंख्या घनत्व और कृषि के लिए पानी की आवश्यकता के मद्देनजर भारत भू-जल पर बहुत अधिक निर्भर है। जहां तक जल संकट का सवाल है तो यह सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है।

प्रमुख बिंदु

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

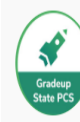
- देश में प्रमुख जल क्षेत्र के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम में किस प्रकार फिलहाल भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है और भविष्य में प्रौद्योगिकी को अपनाने में
- रिपोर्ट के अनुसार, जल संकट से निपटने के लिए उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग, सर्वेक्षण एवं मैपिंग, GPS आधारित उपकरण एवं सेंसर, GIS एवं स्पेशियल एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, रोबोटिक्स और डिजिटल ट्विन जैसी भू-स्थानिक एवं डिजिटल तकनीकों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारत में जल परियोजनाएं:

- राष्ट्रीय नदी जोड़ने की परियोजना
- जल जीवन मिशन
- बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना
- नमामि गंगे मिशन



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



- राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम
 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
 - कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)
 - राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम
 - नदी बेसिन प्रबंधन
 - राष्ट्रीय जल मिशन
 - अटल भूजल योजना
- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के बारे में:**

- यह एक शब्द है जिसका उपयोग पृथ्वी और मानव समाज के भौगोलिक मानचित्रण और विश्लेषण में योगदान करने वाले आधुनिक उपकरणों की श्रेणी का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
- इसे भौगोलिक जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने और संग्रहीत करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।

सबसे आम भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां:

- रिमोट सेंसिंग
- जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम्स (GIS)
- ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS)
- इंटरनेट मैपिंग टेक्नोलॉजीज

स्रोत: PIB

2. मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए गठित आयोग के कार्यकाल में विस्तार को मंजरी दी



चर्चा में क्यों?



- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भीतर उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 31 जुलाई 2021 से आगे 6 महीने के लिए और 31 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहने वाले ग्यारहवें विस्तार को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु लाभ

- इस "आयोग" के कार्यकाल और इसके संदर्भ की शर्तों में प्रस्तावित विस्तार इसे विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा।

आयोग (रोहिणी आयोग):

- आयोग 2 अक्टूबर 2017, राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित किया गया था।
- आयोग सेवानिवृत्त दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश श्रीमती जी रोहिणी की अध्यक्षता में है।
- यह सभी OBC समुदायों के बीच प्रतिनिधित्व का "समान वितरण" सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण के लिए OBC के भीतर श्रेणियां बनाने की संभावना की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था।

नोट:

- वर्तमान में, OBC को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जाता है।
- केन्द्रीय सूची में 2,633 अन्य पिछड़ी जातियां हैं और इस साल की शुरुआत में आयोग ने उन्हें चार उपश्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, जिनकी संख्या 1, 2, 3 और 4 थी और 27% को क्रमशः 2, 6, 9 और 10% में विभाजित किया गया था।
- आयोग ने सभी OBC रिकॉर्ड के पूर्ण डिजिटलीकरण और OBC प्रमाण पत्र जारी करने की एक मानकीकृत प्रणाली की भी सिफारिश की थी।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340:

- राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने के लिये तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान के लिये एक

नोट: सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था। इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, 1955 या काका कालेलकर आयोग के रूप में भी जाना जाता है।

स्रोत: PIB



Follow us on
Telegram

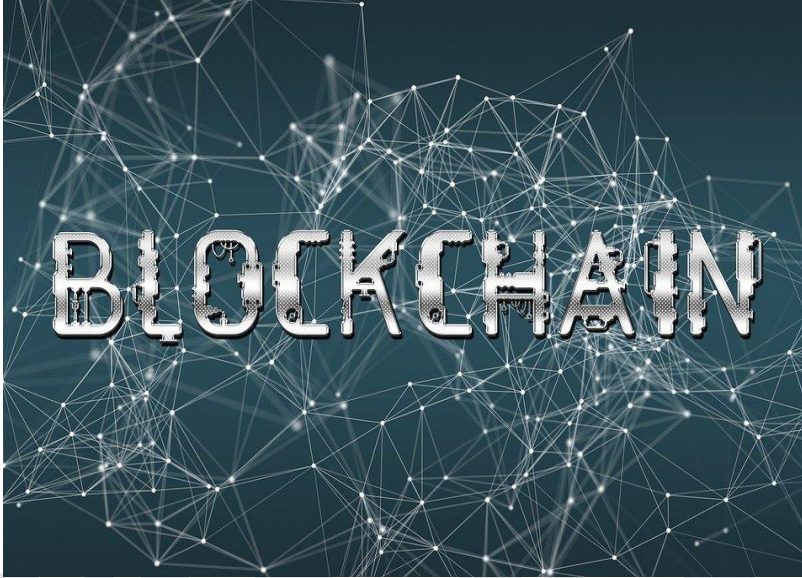


Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



3. महाराष्ट्र ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य होगा



चर्चा में क्यों?

- महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन-संचालित शैक्षिक दस्तावेजों को शुरू करने वाला सिंगापुर, माल्टा और बहरीन के बाद चौथा देश बन गया।

प्रमुख बिंदु

- महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री ने बताया कि इस तकनीक का इस्तेमाल कर दस लाख डिप्लोमा सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे।
- यह तकनीक LegitDoc द्वारा प्रदान की जाएगी।

LegitDoc के बारे में:

- LegitDoc, बंगलौर स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी क्रॉसफोर्ज सॉल्यूशंस का प्रमुख उत्पाद है जो ब्लॉकचेन DApp विकास में विशेषज्ञता रखता है।
- LegitDoc टैम्पर-प्रूफ डिजिटल दस्तावेज जारी करने और सत्यापित करने के लिए एक एथेरियम-आधारित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है।

ब्लॉकचेन के बारे में:

- ब्लॉकचेन एक तरह से जानकारी रिकॉर्ड करने की एक प्रणाली है जिससे सिस्टम को बदलना, हैक करना या धोखा देना मुश्किल या असंभव हो जाता है।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड



4. सरकार ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया



चर्चा में क्यों?

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) 1989 में संशोधन किया है। इस में पुराने वाहनों की विरासत को

संरक्षित और बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु

विंटेज मोटर वाहनों के बारे में:

- मसौदा नियम विंटेज मोटर वाहनों को उन सभी वाहनों के रूप में परिभाषित करते हैं जो दोपहिया और चार पहिया वाहन हैं और उनके पहले पंजीकरण (आयातित वाहन सहित) की तारीख से 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
- विंटेज मोटर वाहनों को नियमित/व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सड़कों पर नहीं चलाया जाएगा।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

5. गुजरात उच्च न्यायालय अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने के लिए देश का पहला उच्च न्यायालय बना



चर्चा में क्यों?

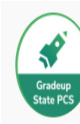
- गुजरात उच्च न्यायालय अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग (सीधा प्रसारण) शुरू करने के लिए देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया।

प्रमुख बिंदु

- भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने गुजरात उच्च न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का उद्घाटन किया।



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



- मुख्य न्यायाधीश ने "गुजरात उच्च न्यायालय (अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2021" भी जारी किया।

गुजरात उच्च न्यायालय के बारे में:

- यह 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य से गुजरात राज्य के विभाजन के बाद बॉम्बे री-ऑर्गनाइजेशन एक्ट, 1960 के तहत स्थापित किया गया था।
- गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश: विक्रम नाथ

स्रोत: TOI

6. भारत सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की शुरुआत की



चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की दो श्रेणियां हैं, पहले में लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर/सेवा प्रदाता शामिल हैं और दूसरी विभिन्न उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल

विभिन्न कंपनियों को पहचान मिलेगी।

प्रमुख बिंदु
पुरस्कारों के बारे में:

- इन पुरस्कारों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है, जिन्होंने अन्य उपलब्धियों के साथ ही परिचालन उत्कृष्टता हासिल की है, डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी को अपनाया है, ग्राहक सेवा में सुधार किया है और निर्यात प्रतिष्ठानों को लाभ दिया है।
- उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए, ये पुरस्कार आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव, आपूर्ति व्यवस्था का विकास, कौशल विकास, स्वचालन और अन्य ऐसे कार्यों की दिशा में किए गए प्रयासों का प्रदर्शन किया जाएगा।

नोट:

- भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र जहां 2020 में लगभग 215 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के साथ 10.5 प्रतिशत CAGR दर से बढ़ रहा है, वहीं इसके साथ ही व्यवस्थित, एक दसरे से जुड़ी समस्याएं हैं जिन्हें उसकी दक्षता में सुधार के लिए दूर किया जाना चाहिए।



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



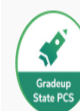
- भारत के GDP में लॉजिस्टिक की समग्र लागत लगभग 14 प्रतिशत आती है। 8 प्रतिशत के वैश्विक औसत की तुलना में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता के अंतर को कम करने के लिए भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र को वैश्विक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में शीर्ष 25 देशों में शामिल होने की महत्वाकांक्षा के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तरह उन्नत, संगठित और कुशल बनाना होगा।

स्रोत: PIB

gradeup



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now

